

कार्यालय आदेश 05/2009

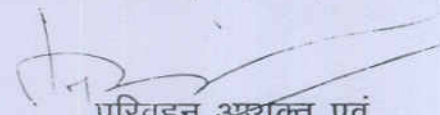
विषय :- नियम विरुद्ध डीजल फ्यूल टैंक की क्षमता बढ़ाने वाले ट्रकों के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में।

सामान्यतः ट्रकों में मूल डीजल टैंक की क्षमता 250-300 लीटर होती है। केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 126 के तहत प्रत्येक वाहन निर्माता को उसके द्वारा निर्मित वाहन का प्रोटोटाईप अनुमोदन उक्त नियम में विनिर्दिष्ट जांच एजेन्सी से करवाना आवश्यक है। जांच एजेन्सी उक्त मॉडल के वाहन के फ्यूल टैंक की क्षमता भी अनुमोदित करती है। नियमानुसार मूल फ्यूल टैंक की क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि पड़ोसी राज्य में डीजल की कम दर होने के कारण कतिपय ट्रक मालिकों ने अपने वाहनों के डीजल टैंक में बदलाव कर टैंक की क्षमता 800 लीटर तक की कर ली है। इसके अतिरिक्त अनेक ट्रकों में नियम विरुद्ध अतिरिक्त फ्यूल टैंक वाहन के दूसरी तरफ लगा रखा है। डीजल टैंक में परिवर्तन करना नियम विरुद्ध होने के साथ ही असुरक्षित भी है। वृद्धिकृत फ्यूल टैंक क्षमता होने के कारण वाहन स्वामी डीजल की अधिकांश खरीद राजस्थान राज्य के बाहर से करता है तथा इससे राज्य में डीजल की बिक्री प्रभावित होती है एवं राज्य सरकार को डीजल पर मिलने वाले वैट की राजस्व हानि होती है।

अतः उपरोक्त संबंध में निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. वाहन को यांत्रिक फिटनेस के समय जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन में अनुमोदित क्षमता वाला ही फ्यूल टैंक लगा हो तथा कोई अतिरिक्त फ्यूल टैंक वाहन में नहीं लगा हो।
2. यदि चैकिंग के दौरान किसी वाहन के मूल फ्यूल टैंक में परिवर्तन पाया जावे अथवा वाहन में अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगा पाया जावे तो निरीक्षक द्वारा उपरोक्त वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। राज्य के सभी कर संग्रह केन्द्रों पर पदस्थापित निरीक्षकगण उपरोक्त वर्णित वाहनों की विशेष रूप से जांच करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे अतः संबंधित निरीक्षक/अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रिया में लाई जावेगी।


परिवहन आयुक्त एवं
प्रदेश शासन सचिव

क्रमांक :- प 7 (53) परि/नियम/मु0/06/पार्ट-II 29/56 जयपुर, दिनांक : 13/03/20

प्रतिलिपि:-

1. समस्त प्रादेशिक/अति0 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
2. समस्त जिला परिवहन अधिकारी
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण
4. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र.....
5. समस्त निजी फिटनेस सेन्टर
6. रक्षित पत्रावली ।

13/3/20
उपायुक्त (नियम)